Seventeenth Loksabha

>

Title:Regarding demands of farmers for legal guarantee of MSP for agricultural produce-laid

श्री विवेक नारायण शेजवलकर (ग्वालियर) : MSP गारंटी कानून लाने की आंदोलनकारियों की मांग अव्यवहारिक और किसानों के हित में नहीं है । पूर्व में ही गठित समिति समय-समय पर कृषि उपज का MSP तय करती है, इससे लगातार वृद्धि भी हो रही है । किसी व्यापारी या उपभोक्ता को उत्पादक से उसका उत्पाद निश्चित मूल्य पर खरीदने हेतु बाध्य कैसे किया जा सकता है । उदाहरण के तौर पर एक पेन दस रूपये से कम पर नहीं खरीदा जा सकता । इसकी गारंटी सरकार कैसे और किस किसको देगी ?

MSP गारंटी कानून का मतलब कृषि उत्पादन के व्यापार का सरकारीकरण होगा जो किसानों के हित में नहीं हैं । ऐसा अव्यवहारिक कानून होगा जिसका कार्यान्वयन असंभव है । आंदोलनकारी किसान नेता MSP गारंटी कानून की मांग सरकार पर अनुचित दबाव डालने हेतु कर रहे हैं । इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा, सरकार इसे प्रोत्साहन न दे ।